

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 11

अंक : 23

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित



3 नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में ...

4 चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन बढ़ती ...

7 ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने किया मैक्सवेल ...

‘अजित दादा’ पंचतत्व में विलीन

‘मिया’ शब्द को लेकर सीएम सरमा का विपक्ष पर हमला, कहा- पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश

परिवार समेत समर्थकों ने नम आंखों से दी विदाई; अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

बारामती। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को गुरुवार को उनके गुहनगर बारामती में अंतिम विदाई दी गई। एक दुःखद विमान हादसे में उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में भारी संख्या में समर्थक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

‘अजित दादा अमर रहें’ के नारे से गुंजा बारामती

अंतिम संस्कार की रस्में दोपहर में शुरू हुईं। अजित पवार के बेटों, पार्थ और जय ने अपने पिता की चिता को मुखर्गिन दी। इस दौरान उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं। जब उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ उनके गांव काटेवाड़ी से विद्या प्रतिष्ठान मैदान लाया गया। मैदान में मौजूद हजारों लोगों ने ‘अजित दादा अमर रहें’ के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया।

अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई केंद्रीय मंत्री

इस दुःखद घड़ी में देश और राज्य के

कई बड़े नेता बारामती पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मुरलीधर मोहोले और भाजपा अध्यक्ष जैस दिग्गज नेता भी शामिल हुए। श्रद्धांजलि दी। अजित पवार के चाचा और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार भी वहां मौजूद थे। वे पूरे समय चुपचाप बैठे रहे और अपने भतीजे को अंतिम



विदाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पुणे से बारामती पहुंचे और पुष्पचक्र अर्पित किए। अजित पवार की चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले पूरे समय सुनेत्रा पवार के साथ खड़ी रहीं और उन्हें सांत्वना देती रहीं। अंतिम संस्कार में

प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, गोवा गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मुरलीधर मोहोले और भाजपा अध्यक्ष जैस दिग्गज नेता भी शामिल हुए। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी काटेवाड़ी जाकर अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता रितेश देशमुख

भी इस मौके पर मौजूद थे। अजित पवार अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। अंतिम संस्कार के दौरान लाउडस्पीकर से बार-बार लोगों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन ने कहा कि शांति बनाए रखना ही ‘दादा’ के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अजित पवार के

भाई श्रीनिवास पवार, बहनें और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें नमन किया।

कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा बुधवार को तब हुआ जब अजित पवार का विमान बारामती एयरस्ट्रिप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान लैंडिंग से महज 200 मीटर पहले गिर गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार के साथ चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। मृतकों में पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शामबी पाठक, सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थे। इन सभी के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

ब्लैक बॉक्स हुआ बरामद हादसे की जांच के लिए पुलिस ने आकस्मिक मौत (एडीआर) का मामला दर्ज किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं, जिससे हादसे की असली वजह पता चल सकेगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, खराब विजिबिलिटी की वजह से विमान को लैंडिंग में दिक्कत हुई थी।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अवसर अवैध बांग्लादेशी शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए ‘मिया’ शब्द का उपयोग करते हैं। विपक्ष इस शब्द को लेकर लगातार उन पर निशाना साधता है और राज्य में सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है। विपक्ष के इस आरोप पर गुरुवार को सीएम सरमा ने पलटवार किया।

‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ें विपक्ष’

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोग इस शब्द को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लेना चाहिए, जिसमें राज्य में हो रहे चुपचाप और भेदभावपूर्ण जनसांख्यिकीय अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शब्द उनकी निजी भाषा या कल्पना नहीं है और न ही कोई राजनीतिक अतिशयोक्ति

है। उनका प्रयास असम की पहचान, बिस्वा सरमा अवसर अवैध बांग्लादेशी शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए ‘मिया’ शब्द का उपयोग करते हैं। विपक्ष इस शब्द को लेकर लगातार उन पर निशाना साधता है और राज्य में सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है। विपक्ष के इस आरोप पर गुरुवार को सीएम सरमा ने पलटवार किया।

‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ें विपक्ष’

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोग इस शब्द को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लेना चाहिए, जिसमें राज्य में हो रहे चुपचाप और भेदभावपूर्ण जनसांख्यिकीय अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शब्द उनकी निजी भाषा या कल्पना नहीं है और न ही कोई राजनीतिक अतिशयोक्ति

की आमद इन जिलों को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल रही है। इससे परिणामस्वरूप बांग्लादेश से इनके विलय की मांग उठ सकती है। निचले असम के हाथ से निकल जाने पर उत्तर-पूर्वी भारत का भूभाग शेष भारत से अलग हो जाएगा और

क्षेत्र वे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के लिए खो जाएंगे।

असम में दशकों से चली आ रही समस्या

सीएम ने कहा कि जब सर्वाच्च न्यायालय ‘जनसांख्यिकीय अतिक्रमण’ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है और क्षेत्र व राष्ट्रीय एकता

के संभावित नुकसान की चेतावनी देता है, तो इसे स्वीकार करना किसी समुदाय के खिलाफ घृणा या सांप्रदायिकता नहीं है। यह असम में दशकों से चली आ रही गंभीर समस्या की वास्तविकता को दर्शाता है।



असम में दशकों से चली आ रही समस्या

सीएम ने कहा कि जब सर्वाच्च न्यायालय ‘जनसांख्यिकीय अतिक्रमण’ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है और क्षेत्र व राष्ट्रीय एकता

कर्नाटक सरकार का फैसला, सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का नहीं कर सकते इलाज

बंगलूरु। बिहार के बाद कर्नाटक ने भी सरकारी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में इलाज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने गुरुवार को कहा कि सरकारी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को अपने नियमित सरकारी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद निजी क्लीनिकों अथवा अस्पतालों के केवल बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में



ही सेवा देने की अनुमति है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में नियमित सरकारी कार्य बाधित न हो। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को निजी अस्पतालों में इस तरह की अपनी सेवा के बारे में पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

देश की 97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में भारतनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध: ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देशभर की 97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में भारतनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सिंधिया ने कहा कि भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और इसे चरणबद्ध तरीके से देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘भारतनेट-एक और दो परियोजनाओं के तहत चिन्हित लगभग 2,22,000 ग्राम पंचायतों में से

2,15,000 ग्राम पंचायतों को पहले ही कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। इसका अर्थ है कि 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 100 प्रतिशत



कावरेज हासिल न हो पाने के पीछे कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, उनसे जुड़ी कठिनाइयां और वामपंथी उग्रवाद जैसे चुनौतियां प्रमुख कारण हैं। उन्होंने

बताया कि शेष लगभग तीन प्रतिशत लक्ष्य, यानी करीब 7,000 ग्राम पंचायतों में अब तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ये क्षेत्र अत्यंत पहाड़ी, दुर्गम हैं और कुछ स्थानों पर वामपंथी उग्रवाद की समस्या भी है।

सिंधिया ने कहा कि परियोजना के शुरुआती चरण में ‘राइट ऑफ वे’ प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस संबंध में राजपत्रित अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि ‘राइट ऑफ वे’ का तात्पर्य सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा बुनियादी ढांचे की स्थापना करने और उनके संचालन से जुड़े नियमों और

अधिकारों से है। सिंधिया ने कहा कि अब संबंधित राज्य सरकारों को यह बताया जा रहा है कि ‘राइट ऑफ वे’ प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। भारतनेट परियोजना को 25 अक्टूबर 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन एक विशेष प्रयोजन इकाई ‘भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड’ (बीबीएनएल) द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 2012 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2016 को दूरसंचार आयोग ने इस परियोजना को तीन चरणों में लागू करने की स्वीकृति दी थी।

टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई जान,एम.के. स्टालिन ने की 20 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी की घोषणा

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को कपड़ा क्षेत्र को और मजबूत करने के तमिलनाडु सरकार के प्रयासों के तहत उन्नत कपड़ा और परिधान मशीनरी की खरीद पर 20 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी की घोषणा की। कोयंबटूर के कोडिसिया व्यापार मेला परिसर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ शासन मॉडल के तहत, कपड़ा क्षेत्र ने ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी और जूते निर्माण जैसे क्षेत्रों के बराबर तीव्र वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला

कि तमिलनाडु पिछले पांच वर्षों से भारत का सबसे बड़ा रेडीमेड वस्त्र निर्यातक रहा है, जो देश के कुल वस्त्र व्यापार का 33 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने कहा



कि यह क्षेत्र 31 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष में रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण में इस क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करता है।

राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए एक अलग वस्त्र विभाग की गठन का उल्लेख करते हुए, स्टालिन ने तमिलनाडु के वस्त्र उद्योग को वैश्विक

स्तर पर स्थापित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए हथकरघा और वस्त्र मंत्री आर गांधी और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत

टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, जिनमें नए बाजारों की खोज करना और केंद्र सरकार से कपास पर लगे 11 प्रतिशत आयात शुल्क को वापस लेने का आग्रह करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा, विशेष रूप से भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के संदर्भ में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु की नई एकीकृत वस्त्र नीति 2025-26 का विमोचन किया गया। उद्योग जगत के हितधारकों की मांगों के जवाब में, स्टालिन ने अत्याधुनिक बुनाई और सिलाई मशीनों की खरीद के लिए 20 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी की घोषणा की, जिसके लिए योजना के तहत प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मौत का तांडव, 21 शव बरामद, 28 लापता; बीजेपी बोली- टीएमसी सरकार की लापरवाही

कोलकाता। कोलकाता के पास 26 जनवरी को लगी आग में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है, जल्द हुए भवनों से 13 और शव बरामद किए गए हैं। 28 अन्य लोग अभी भी लापता हैं, और

आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस ने इलाके में सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा भी लागू कर दी है। तड़के दक्षिण 24 परगना जिले के आनंदपुर में लगी भीषण आग दो गोदामों और एक मोमो कंपनी की निर्माण इकाई तक फैल गई। मृतकों की संख्या अब बढ़कर 21 हो गई है, जिनमें से 13 से अधिक शव इमारतों से बरामद किए गए हैं। घटना की प्रकृति और क्षति की सीमा को देखते हुए, मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंद्र

अधिकारी ने गुरुवार को आग से प्रभावित नाजिराबाद क्षेत्र का दौरा किया, जहां बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, लेकिन उन्होंने वास्तविक घटनास्थल में प्रवेश करने



से परहेज किया और कहा कि वह कानून का पालन करेंगे। आधी रात से इलाके में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। अधिकारी ने सरकार पर ‘लापरवाही’ बरतने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि दमकल सेवाएं घटनास्थल पर देर से

पहुंचीं। उन्होंने दावा किया, ‘इस घटना के बाद भी टीएमसी सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार विपक्षी नेता को घटनास्थल पर जाने से रोकने के लिए इतनी सक्रिय है, तो मंत्रियों और टीएमसी नेताओं को वहां जाने की अनुमति क्यों दी गई? भाजपा नेता के हवाले से यह बात कही गई है।

सोमवार को लगी भीषण आग ने गोदामों और एक विनिर्माण इकाई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे जली हुई इमारतें और श्रमिकों के शव भी बचे। इससे

पहले, अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए 21 शवों या शरीर के अंगों की पहचान स्थापित करने के लिए गुरुवार से डीएनए मैपिंग शुरू होने की संभावना है। पुलिस ने इस मामले में यथासंभव अधिक से अधिक शवों की पहचान करना अत्यावश्यक बताया।

महिला रोजगार योजना के लाभुकों को दो लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया शुरू : नीतीश कुमार

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित लाभुकों को दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, बशर्ते पूर्व में दी गई सहायता राशि का सदुपयोग कर लाभुकों ने रोजगार शुरू किया हो।

उन्होंने कहा कि यदि पहचान करना अत्यावश्यक बताया।

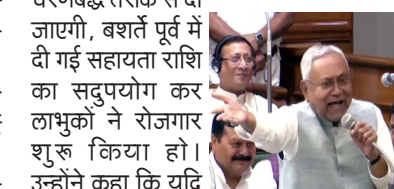
राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला, उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके।”

उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपए की राशि दी गई है। अब तक एक करोड़ 56 लाख लाभुकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष रोजगार संचार रूप से चल रहा हो तो आवश्यकता के अनुसार एकमुश्त राशि भी प्रदान की जा सकती है। नीतीश कुमार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य



में नई उप महापौर चुनी गई हैं। महापौर पद के लिए मतदान का विवरण सौरभ जोशी (भाजपा) को 18 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के योगेश ढिंगरा को 11 और कांग्रेस के गुरूप्रीत सिंह गब्बी को 7 वोट मिले—जिनमें मौजूदा सांसद मनोष तिवारी का समर्थन भी शामिल है। भाजपा के वोटों की संख्या 35 सदस्यीय सदन में उसके 18 पार्षदों की संख्या के बराबर है।

पारदर्शी हाथ उठाकर मतदान प्रक्रिया चुनाव में गुप्त मतदान की जगह हाथ उठाकर मौखिक पुष्टि की गई, जिसकी देखरेख मनोनीत पार्षद रामनील सिंह बेदी ने पीठासीन अधिकारी के रूप में की। इस खुली पद्धति से भाजपा के 18, आम आदमी पार्टी के 11, कांग्रेस के 6 सदस्यों और सांसद के पदेन वोट के कारण क्रांति-वोटिंग का खतरा कम हो गया।



मुंबई की जहरीली हवा पर हाईकोर्ट सख्त, निगरानी के लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी; रोज होगी समीक्षा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक उच्चस्तरीय (हाई-पावर) समिति गठित करने का फैसला किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब तक राज्य और नगर निकायों द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी हैं और आम लोगों को शुद्ध हवा में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि परिणाम सुनिश्चित करना चाहता है।

क्या है अदालत की चिंता?
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि अक्टूबर 2023 में स्वतः संज्ञान लेने के बाद से हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। नवंबर 2023 में अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए थे, लेकिन ज़मीनी असर नजर नहीं

आया। दिसंबर में प्रदूषण स्तर 'बहुत गंभीर' तक पहुंचने की रिपोर्ट ने अदालत की चिंता बढ़ाई।
अब तक के कदम क्यों नाकाम रहे?
अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई-नवी मुंबई



की नगरपालिकाओं की ओर से दाखिल हलफनामे पर्याप्त नहीं हैं। प्रयास किए गए होंगे, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। कोर्ट ने यह भी माना कि बढ़ते मामलों और सीमित

समय के कारण हर हलफनामे की सूक्ष्म जांच संभव नहीं, इसलिए निगरानी के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है।
हाई-पावर कमेटी क्या करेगी?
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट

वेग एक पूर्व न्यायाधीश करेगी। समिति रोजाना बैठक कर अनुपालन की समीक्षा करेगी। नगर निकायों और संबंधित एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट तलब करेगी। जरूरी सुविधाएं और अधिकार समिति को दिए जाएंगे, ताकि निर्णय लागू हो सकें।
नागरिकों को मुआवजे का संकेत
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि प्रदूषण से प्रभावित नागरिकों को

मुआवजा देने के सुझाव पर विचार हो सकता है। नवी मुंबई नगर निगम की ओर से मौजूदा वैधानिक निकायों का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कार्यवाही में ऐसे निकायों की ठोस कार्यवाई सामने नहीं आई, इसलिए समिति को कुछ अधिकार देना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि समिति के सदस्यों के नाम लिखित आदेश में तय किए जाएंगे। उद्देश्य स्पष्ट है केवल कागजी कार्यवाई नहीं, बल्कि वास्तविक सुधार। अदालत ने दोहराया कि मुंबई जैसे महानगर में प्रदूषण कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए और सभी एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। मुंबई में वायु गुणवत्ता का लगातार बिगड़ना स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अदालत का यह कदम निगरानी, जवाबदेही और परिणाम-आधारित कार्यवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे शहरी हवा की गुणवत्ता में ठोस सुधार की उम्मीद जगी है।

पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल एवं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में ट्रैफिक गेटमैन एवं पॉइंट्समैन के पदों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती हेतु पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल एवं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन के मध्य एक

रूप में तैनाती करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल है। इसके साथ ही रतलाम मंडल उन चुनिंदा मंडलों में शामिल हो गया है, जहां इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ऑर्गनाइजेशन की ओर से कर्नल श्री मुकेश कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त) ने हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के अंतर्गत चयनित पूर्व सैनिकों की भौतिक तैनाती आगामी 15 दिनों के



महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 29 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किए गए। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत रतलाम मंडल के विभिन्न स्थानों पर पूर्व सैनिकों को ट्रैफिक पॉइंट्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से लगभग 100 ट्रैफिक पॉइंट्समैन का नियोजन प्रस्तावित है। यह समझौता मंडल रेल प्रबंधक, रतलाम श्री अश्वनी कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का परिणाम है।

इस समझौते के साथ ही रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे का पहला ऐसा मंडल बन गया है, जिसने इस प्रकार का एमओयू कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार रेलवे में पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के

भीतर प्रारंभ की जाएगा। यह समझौता दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक एवं फलदायी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे रेल परिवालन की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्रालय में दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि

कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासनित और समयनिष्ठ नेतृत्व का हुआ निधन– अपर मुख्य सचिव विकास खड्गे

दिव्यांश

राज्य के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के अवसर पर मंत्रालय के त्रिमूर्ति परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से आयोजित शोकसभा में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने सेवाकाल के दौरान सरकार की कर्तव्यों का ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यभाव से निर्वहन किया। उनके निधन से राज्य सरकार ने एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और समयनिष्ठ नेतृत्व खो दिया है, ऐसा शोक व्यक्त करते

हए अपर मुख्य सचिव विकास खड्गे ने उपस्थित जनों की ओर से कहा। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉ. इकबाल सिंह चहल, मनीषा म्हेस्कर, अश्विनी भिड़े, असीम कुमारा गुप्ता, विकास चंद्र रस्तोगी, वैष्णुगोपाल रेड्डी, अनुप कुमार सिंह, राधिका रस्तोगी, एकनाथ दावल, सौरभ विजय, डॉ. हर्षदीप कांबले, अतुल पाटणे, संजय खंडारे, एस. चोक्कलिंगम, रणजीतसिंह देओल, विरेंद्र सिंह, गणेश पाटिल, संतोष कुमार, दिलीप घुमरे, जयश्री भोज, अंशु सिन्हा, राजेश गावंडे,

विजय वाघमारे तथा मकरंद देशमुख सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिवंगत अजित पवार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई तथा उन्हें इस गहरे दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर मंत्रालय के बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए।

निरीक्षक को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान

के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया गया है। उनकी सेवाएं रेलवे सुरक्षा बल के मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करती हैं। यह सम्मान न केवल श्री अनवर हुसैन के लिए, बल्कि सम्पूर्ण रेलवे सुरक्षा बल के लिए गौरव का विषय है तथा यह आरपीएफ कर्मियों द्वारा राष्ट्र सेवा में दिए जा रहे सतत योगदान का प्रमाण है।



सफाले और केलवे रोड के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें होंगी प्रभावित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पुल संख्या 114 पर गर्डरों के डी-लॉचिंग कार्य के लिए सफाले और केलवे रोड के बीच निम्न कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक लिया जाएगा। 31 जनवरी, 2026 को अप लाइन पर 02:15 बजे से 03:15 बजे तक तथा डाउन लाइन पर 01:45 बजे से 05:45 बजे तक ब्लॉक रहेगा। 01 फरवरी, 2026 को अप लाइन पर 00:30 बजे से 04:30 बजे तक तथा डाउन लाइन पर 00:30 बजे से 04:00 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। इसी प्रकार, उपर्युक्त अवधि के दौरान कुछ ट्रेन सेवाएँ प्रभावित रहेंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है: निरस्त होने वाली ट्रेनें:

- 31 जनवरी, 2026 को दहानू रोड से 07:00 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93006 दहानू रोड-विरार मेमू
- 31 जनवरी, 2026 को विरार से 04:50 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन

संख्या 93001 विरार-दहानू रोड मेमू रेगुलर/रिश्डेचुल होने वाली ट्रेनें:

- 31 जनवरी, 2026 को विरार से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 69141 विरार-सूरत मेमू 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 30 जनवरी, 2026 को बरौनी से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 30 एवं 31 जनवरी, 2026 को ओखा से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल मेल एक्सप्रेस क्रमशः 30 मिनट तथा 1 घंटा 10 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को भुज से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22904 भुज-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को भुसावल से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09052 भुसावल-दादर स्पेशल 50 मिनट

रेगुलेट होगी।

- 31 जनवरी, 2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22928 अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 45 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को वेरावल से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19218 वेरावल-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 45 मिनट



रेगुलेट होगी।

- 31 जनवरी, 2026 को एकता नगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकता नगर-दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 40 मिनट रेगुलेट होगी।
- 30 जनवरी, 2026 को श्री गंगानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या

14701 श्री गंगानगर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

- 31 जनवरी, 2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद-दादर एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को इंदौर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12962 इंदौर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को इंदौर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को भगत की कोठी से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 31 जनवरी, 2026 को हनुमानगढ़ से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।
- 01 फरवरी, 2026 को दहानू रोड से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या

69174 दहानू रोड-बोरीवली मेमू 30 मिनट रेगुलेट होगी।

- 31 जनवरी, 2026 को दादर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12927 दादर-एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट रेगुलेट होगी।

31 जनवरी, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22923 बांद्रा टर्मिनस-जामनगर एक्सप्रेस 1 घंटा रेगुलेट होगी।

- 01 फरवरी, 2026 को दादर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19003 दादर-भुसावल एक्सप्रेस 50 मिनट रेगुलेट होगी।
- 01 फरवरी, 2026 को बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस 50 मिनट रेगुलेट होगी।

शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें: 1. 31 जनवरी, 2026 को प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19101 विरार-भरूच एक्सप्रेस पालघर से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह ट्रेन विरार और पालघर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी।

विमानन मंत्री ने महाराष्ट्र सीएम फडणवीस को लिखा पत्र, हादसे की जांच में सहयोग मांगा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से सहयोग मांगा, ताकि पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की तेजी से जांच की जा सके। इस विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोग मारे गए थे। पत्र में विमानन मंत्री ने क्या कहा? हादसे के एक दिन बाद विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने दुर्घटनास्थल तक पहुंच, स्थानीय प्रशासनिक मदद और स्थानीय एजेंसियों के साथ तालमेल सहित अन्य कदमों के लिए राज्य सरकार का सहयोग



अजित पवार बुधवार को निजी विमान से मुंबई से अपने पैतृक शहर बारामती जा रहे थे। उनके साथ चार अन्य सवार थे। लेकिन यह विमान बारामती की

टेबलटॉप हवाई पट्टी (एयरस्ट्रिप) से करीब दो सौ मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच पाया। हादसे में अजित पवार के अलावा कौन लोग मारे गए? इस हादसे में अजित पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर (जिनका उड़ान अनुभव 15,000 घंटे का था) सह-पायलट वॉल्टन शांभावी पाठक (जिनका उड़ान अनुभव 1,500 घंटे का था) पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी मारे गए।

फडवीस के आग्रह पर विमानन मंत्री ने क्या कहा? इससे पहले फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया था कि वह इस दुर्घटना का सही कारण पता लगाने के लिए विस्तृत जांच का आदेश दें। उन्होंने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया। नायडू ने कहा कि उनके मंत्रालय ने ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मुख्यमंत्री के अनुरोध को ध्यान में रखा है। उन्होंने आश्चस्त किया कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर जरूरी सुरक्षा सिफारिशें और नियामक या परिचालन संबंधी उपाय एएआईबी, विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और अन्य संबंधित पक्षों के तालमेल में लागू किए जाएंगे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

एल.टी.एम.जी. अस्पताल, सायन, मुंबई - 400 022
क्रमांक: LTH/ET-26/T, दिनांक 29/01/26

ई-निविदा सूचना

यह एक ई-निविदा सूचना है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आयुक्त द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार तीन-पैकेट प्रणाली में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

ई-निविदा की प्रति महा-टेंडर्स पोर्टल (<https://mahatenders.gov.in>) के 'ई-प्रोक्वोरमेंट' अनुभाग से डाउनलोड की जा सकती है।

विषय : एल.टी.एम.जी. अस्पताल के शल्य चिकित्सा विभाग के लिए लैप्रोस्कोपिक हार्मोनिक शियर (मात्रा : 14 शियर) की आपूर्ति। बिड क्रमांक : 2025_MCGM_1258240_1

ई-निविदा शुल्क (₹.)	ईएमडी (₹.)	ऑनलाइन बोली डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
₹. 1,452/- + 18% जीएसटी	₹. 20,000/-	30.01.2026, शाम 04:00 बजे (16:00 घंटे)	05.02.2026, शाम 04:00 बजे (16:00 घंटे)

इच्छुक निविदादाता निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए महा-टेंडर्स पोर्टल वेबसाइट <https://mahatenders.gov.in> पर अवश्य अवलोकन करें। निविदा दस्तावेज डाक द्वारा न तो जारी किए जाएंगे और न ही स्वीकार किए जाएंगे।

पीआरओ/2804/विज्ञा./2025-26

एल.टी.एम.जी. अस्पताल, सायन

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि

जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली



मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार के 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए विमान हादसे में हुए आकस्मिक और दुखद निधन से पूरा देश गहरे शोक में डूब गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि इसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया और विश्वास करना कठिन हो गया।

नवी मुंबई महानगरपालिका की ओर से महानगरपालिका मुख्यालय स्थित एम्फीथिएटर में श्री अजितदादा पवार

की प्रतिमा पर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे द्वारा पुष्पचक्र अर्पित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार, सभी विभाग प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी तथा उपस्थित नागरिक मौजूद थे और सभी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के निर्माण और प्रशासन में अमूल्य योगदान देने वाले श्री अजितदादा पवार जैसे महान नेता का अचानक निधन महाराष्ट्र राज्य और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकसंतप्त परिवार

को इस गहरे दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। आयुक्त ने कहा कि नवी मुंबई महानगरपालिका के मुख्यालय भवन, जिसे एक प्रतिष्ठित (आइकॉनिक) इमारत के रूप में जाना जाता है, के निर्माण में तथा महानगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को गति देने में श्री अजितदादा पवार का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने बताया कि दिवंगत नेता का अचानक निधन महाराष्ट्र राज्य के देखने का अवसर मिला। सातारा में कार्य करते समय उन्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कोविड काल के दौरान, जब बड़ी संख्या में श्रमिक

अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे थे, तब रात 2 बजे भी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने तुरंत सहायता उपलब्ध कराई। आयुक्त ने यह भी स्मरण किया कि सीडको में कार्यरत रहते हुए भी विभिन्न विषयों पर उन्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। इस अवसर पर सभी ने मौन धारण कर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की तथा विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार, उनके सुरक्षा रक्षक श्री विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शंभवी पाठक तथा फ्लाइट अटेंडेंट श्री पिंकी माली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

महाराष्ट्र ने प्रशासन पर गहरी पकड़ रखने वाला एक निडर, कार्यकुशल और सशक्त नेता खो दिया- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डेकर

मुंबई। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजितदादा पवार के आकस्मिक और दुखद निधन की खबर अत्यंत हृदयविदारक है। उनके निधन से

महाराष्ट्र ने प्रशासन पर गहरी पकड़ रखने वाला एक निडर, कार्यकुशल और सशक्त नेता खो दिया है, ऐसा ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डेकर ने कहा।

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डेकर ने अपने शोक संदेश में कहा कि अजितदादा पवार ने सार्वजनिक जीवन में हमेशा स्पष्ट और ठोस भूमिका निभाई। वित्त विभाग के

माध्यम से उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए, वे आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं। प्रशासनिक सूक्ष्मताओं की समझ, आंकड़ों पर उनकी मजबूत पकड़ और निर्णायक नेतृत्व के



कारण वे एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने हमेशा विकास के मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण बनाए रखा। अजितदादा राजनीति से ऊपर उठकर

व्यक्तिगत संबंध निभाने वाले, सहयोगियों से संवाद बनाए रखने वाले और कार्य में ईमानदारी रखने वाले नेता के रूप में भी पहचाने जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके निधन से राज्य

की राजनीति और प्रशासन में जो शून्य उत्पन्न हुआ है, उसकी भरपाई असंभव है।

इस कठिन समय में हम पवार परिवार के दुःख में सहभागी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की

शक्ति दे। महाराष्ट्र की ओर से अजितदादा पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह शोक संदेश राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डेकर ने दिया।

अजित पवार के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, जानिए क्या थे क्रू के अंतिम शब्द

मुंबई। बारामती में हुए चार्टर विमान हादसे की जांच जारी है। इस बीच दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और उड़ान डेटा रिकॉर्डर दोनों सुरक्षित रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार, 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में निधन हो गया था। इस दर्दनाक घटना के एक दिन बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, जिस स्थान पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और फोरेंसिक विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। टीमों ने पूरे घटनास्थल की गहन जांच की है। चार्टर्ड लर्नजेट पैतालीस विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद

इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि यदि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स और उड़ान डेटा मिल जाता है, तो हादसे की वजह और उससे पहले घटी घटनाओं के सही क्रम का पता लगाया

जा सकेगा। अब दिल्ली स्थित बीएसआर एविएशन कंपनी के चार्टर्ड विमान लर्नजेट पैतालीस का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है।



नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'बारामती के पास हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे के बाद सभी आवश्यक

बचाव एवं जांच व्यवस्थाएं तुरंत सक्रिय कर दी गई थीं। पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो,



दिल्ली से तीन अधिकारियों की एक टीम तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से तीन अधिकारियों की एक अन्य टीम 28 जनवरी को घटनास्थल पर पहुंची। विमान दुर्घटना

जांच ब्यूरो के महानिदेशक भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है।



जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर, मानक संचालन प्रक्रिया और तय दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। यह जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो नियम, 2025 के नियम पांच और ग्यारह

के अंतर्गत शुरू की गई है।' नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारी और फोरेंसिक टीमें गुरुवार को बारामती में दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं। वहीं पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस हादसे के संबंध में बारामती तालुका पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना से पहले क्रू के अंतिम शब्द क्या थे?

इस हादसे को लेकर कई तरह की जानकारीयां सामने आ रही हैं, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस बीच मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दुर्घटना से ठीक पहले क्रू के अंतिम शब्द थे- 'ओह शिट' 'ओह शिट।' नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज अंतिम बातचीत में यही शब्द सुने गए हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मुख्य पायलट सुमित कपूर द्वारा कोई आपातकालीन संदेश नहीं दिया गया था।

25 जनवरी को गंगापूर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हत्या का प्रयास, लापरवाही से वाहन चलाना और मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित प्रतीत होती है. मामले की गहन जांच की जा रही है और आया कि इन लड़कों का पहले आरोपी से झगड़ा हो चुका था।

की अवधि बढ़ाई है. लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को आकस्मिक निधन होने के कारण राज्य सरकार ने 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक शोक घोषित किया है. इस अवधि को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम के शेष चरणों में बदलाव किया



गया है। 7 फरवरी को सुबह 7.30 बजे से वोटिंग इसके अनुसार संबंधित जिलाधिकारी संशोधित चुनाव कार्यक्रम की सूचना 31 जनवरी 2026 को प्रकाशित करेंगे. अब 7 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा. इसलिए चुनाव प्रचार की समाप्ति करने के चरण शेष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 के बाद केवल दो सप्ताह

परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित स्थानों पर आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी. निर्वाचित सदस्यों के नाम शासन राजपत्र में 11 फरवरी 2026 तक प्रकाशित किए जाएंगे। पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के



साथ डिप्टी सीएम अजित पवार को अंतिम विवाई दी गई. दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखानि दी. उनके निधन से बारामती में भारी शोक की लहर है. अजित पवार 66 साल के थे. बुधवार को उनका विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और लैंडिंग के दौरान क़ैश कर गया. इसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. विमान हादसे की जांच शुरू है।

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के शोक में डूबा राज्य, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य उपस्थित

अधिकारी, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र के मान्यवर तथा राज्यभर से आए बड़ी संख्या में आम नागरिक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने उपस्थित रहे।

अंतिम संस्कार से पूर्व विद्या प्रतिष्ठान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान

‘मुझे गालियां दी गईं, मेरे उपनाम को लेकर अपमान किया गया’

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो बातें प्राकृतिक न्याय के

‘अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों को वापस लेने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह किनारा कर लिया है। यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि उन्हें जनता के विरोध का कोई सम्मान या परवाह नहीं है। और जो लोग उस समय चुप रहे जब आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी थी, उसका निर्णय समय करेगा।’



विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ वह लगातार आवाज उठाती रहेंगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर जनता के विरोध की नोटिस अनदेखी करने का आरोप लगाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगाई है जो अस्पष्ट थे, मनमाने थे और शैक्षणिक परिसरों में अधिक भेदभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। 'मुझे ठोका गया, गालियां दी गईं' - प्रियंका चतुर्वेदी प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए सामाजिक माध्यम 'एक्स' पर लिखा, 'मुझे ठोका गया, गालियां दी गईं और मेरे उपनाम को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह सब सामने आने के बावजूद, जो बातें प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ मैं अपनी आवाज उठाती रहूंगी।' 'सरकार को जनता के विरोध की कोई परवाह नहीं' उन्होंने आगे कहा,

केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस गौरतलब है कि गुरुवार, 29 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर रोक लगा दी है। मामले की आगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि तब तक वर्ष 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम ही लागू रहेंगे। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागरी की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के खंड तीन-सी को चुनौती दी है। उनका कहना था कि नियमों में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वह संविधान के अनुरूप नहीं है।

सम्पादकीय

बारामती विमान हादसा - अजित पवार की मौत ने फिर उठाए सवाल, क्या सबक अब भी नहीं?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की एक विमान हादसे में मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। इस त्रासदी ने न केवल देश के एक कुशल नेता को छीन लिया, बल्कि उन दर्दनाक हादसों की कड़वी यादें भी ताजा कर दीं, जिनमें पहले भी देश ने कई राजनीतिक दिग्गजों और प्रमुख हस्तियों को असमय खोया है। पुणे जिले के बारामती में हुए इस हादसे की अब कई कोणों से जांच की जा रही है, मगर सवाल है कि इससे पहले हुई ऐसी दुर्घटनाओं से क्या सरकारी तंत्र ने कोई सबक नहीं लिया?

आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त हवाई अड्डे पर दृश्यता कम थी। अगर स्थिति वास्तव में जोखिमपूर्ण थी, तो विमान को उतरने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरा, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में क्या ऐसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे जिला के बारामती में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीचे आने के बाद उसमें धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई।

इससे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता संजय गांधी, वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया, वर्ष 2011 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, वर्ष 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वर्ष 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी जैसे दिग्गजों को भी देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है।

कहा जा रहा है कि अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब ‘नहीं’ था। इसके बाद विमान ने आसमान में ही एक वक्कर लगाया। इससे स्पष्ट है कि हवाई अड्डे पर परिस्थितियां विमान को उतारने के अनुकूल नहीं थीं। यह दावा भी किया जा रहा है कि दूसरी बार पुछे जाने पर पायलट ने सकारात्मक जवाब दिया। मगर सवाल है कि क्या किसी तरह के जोखिम का आशंका के बीच विमान को उतारने की अनुमति दी जा सकती है? अजित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उपमुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकल कर उन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी के नाम और चिह्न के साथ-साथ दल के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद वे राजग नीत महायुति में शामिल हो गए थे।

उनके नेतृत्व वाली राकांपा ने हाल में पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुए निकाय चुनाव में शरद पवार की अमुआई वाली पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इसके बाद सियासी गलियारों में अजित पवार और शरद पवार के बीच नजदीकियां बढ़ने की अटकलें भी जोर पकड़ रही थीं। ऐसे में विपक्षी दल इस हादसे की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विमान दुर्घटना की निष्पक्ष और गहन जांच हो, ताकि हादसे के असली कारण सामने आ सकें। सरकारी तंत्र को भी इस तरह के हादसों से सबक लेकर व्यवस्था में जरूरी सुधार करने चाहिए, ताकि भविष्य में और कोई विमान दुर्घटना न हो।



‘एक भारत, एक कानून’ की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ

विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए ‘एक भारत, एक कानून’ की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।

लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से ‘एक देश, एक कानून’ की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान नागरिक संहिता या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी।

यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन

राष्ट्र के दूरगामी भविष्य के लिए इन कपोलकल्पित बाधाओं, वैधानिक जटिलताओं से निबटना भी तो सकारात्मक और आशावादी नेतृत्व की पहचान होती है। खासकर मोदी हैं तो मुमकिन है, वाली सोच यहां भी चरितार्थ की जा सकती है। योगी हैं तो यकीन सकता है कि क्या जा सकता है। शाह हैं तो चिल्लपों भी नहीं मचेगा, ऐसा जनविश्वास है।

जहां तक संघीय ढांचे की चुनौतियों की बात है तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का त्रिपक्षीय विभाजन (केंद्र, राज्य, समवर्ती) एक देश, एक कानून की राह का एक बड़ा रोड़ा समझा जाता है। उदाहरणतया पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे विषय राज्य सूची में हैं, जिनमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा बिना संशोधन के। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 246 इस विभाजन को मजबूत बनाता है, जो एकसमान कानून लागू करने में राज्यों की सहमति या संविधान संशोधन की मांग करता है।

वहीं, मौलिक अधिकारों का टकराव भी संभाव्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते

आज जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो इन चमकदार आंकड़ों के समान्तर खड़ा आर्थिक असमानता का सच चिंताजनक है। यह एक गहरा विरोधाभास है कि जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच की खाई ऐतिहासिक रूप से चौड़ी हो गई है। विकास का मूल्यांकन केवल जीडीपी की वृद्धि दर से करना बेमानी है, क्योंकि यह आंकड़ा संपत्ति के वितरण की नहीं, बल्कि औसत आय की तस्वीर पेश करता है। जमीनी सच्चाई यह है कि देश की बढ़ती संपदा का एक बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर अति-धनाढ्यों की तिजोरियों में जा रहा है, जबकि श्रमशक्ति का एक विशाल वर्ग आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत है। यह असमानता केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस समावेशी विकास के दावों पर एक गंभीर सवाल है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। इस असमानता का सबसे भयानक रूप हमें कोविड महामारी के बाद के समय में देखने को मिला। वह एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया रुक गई थी, लेकिन संपत्ति का खेल नहीं रुका। एक तरफ लाखों मध्य और निम्न-वर्गीय परिवारों की जमा-पूंजी इलाज, प्राणवायु और बेरोजगारी की भेंट चढ़ गई। करोड़ों लोग, जो अपनी मेहनत से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके थे, वापस उसके नीचे धकेल दिए गए। छोटे व्यापार बंद हो गए, नौकरियां चली गईं और प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामूहिक विवेक को झकझोर गईं।

दूसरी तरफ, ठीक इसी कालखंड में देश के शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति में ऐतिहासिक और अकल्पनीय वृद्धि दर्ज की गई। जब आम आदमी कर्ज की मासिक किस्ते चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब शेयर बाजार कुलोंचे भर रहा था। अर्थशास्त्रियों ने इसे ‘विषम सुधार’ का नाम दिया। यह एक ऐसी स्थिति थी, जहां अर्थव्यवस्था दो



विपरीत दिशाओं में बंट गई। एक तरफ संगठित और अमीर वर्ग ऊपर की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ असंगठित और गरीब वर्ग रसतल में जा रहा था।

जब एक आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त होकर अपनी थाली से सब्जियां और दाल कम करने पर मजबूर होता है और उसी वक्त देश में महंगी गाड़ियों तथा विलासिता की वस्तुओं की बिक्री के नए कीर्तिमान बनते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि समाज का संतुलन बिगड़ चुका

है। इस असंतुलन की जड़ें हमारी नीतियों और कर-प्रणाली में भी गहरी धंसी हुई हैं। पिछले कुछ दशकों में उदारीकरण के नाम पर हमने जिस पूंजीवादी ढांचे को अपनाया, उसका मूल मंत्र था- ‘रिसाव का सिद्धांत’। यह माना गया था कि अगर हम ऊपर के लोगों और बड़े निगमित दांचों को समृद्ध करेंगे, उन्हें करेंगे में छूट देंगे, तो वे निवेश करेंगे और उसका

वे गरीब और अमीर पर लगभग एक समान बोझ डालते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कर संग्रह का बड़ा हिस्सा निचले और मध्य वर्ग की जेब से आता है। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली लाखों-करोड़ों रुपए की कर छूट और कर्ज माफी को अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए ‘प्रोत्साहन’ का नाम दिया जाता है। दूसरी ओर, जब किसानों की कर्ज माफी, वृद्धावस्था पेंशन या गरीबों के

बेहतर इलाज हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए, न कि केवल उन लोगों का विशेषाधिकार जो इसे खरीद सकें। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों के लिए एक महंगा सौदा बन चुकी हैं। जब एक गरीब परिवार का प्रतिभाशाली बच्चा केवल संसाधनों, अतिरिक्त शिक्षण और अच्छी किताबों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो देश केवल एक व्यक्ति का भविष्य नहीं खोता, बल्कि अपनी एक संभावना को खो देता है।

इतिहास गवाह है कि जब धन का अत्यधिक संकेंद्रण होता है, तो सत्ता और राजनीति भी उसी धन के प्रभाव में आ जाती है। ऐसे में नीतियां आम जनता, किसान और मजदूर के हितों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों के मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बनाई जाने लगती हैं। आज चुनाव, जो लोकतंत्र का उत्सव माने जाते हैं, इतने महंगे हो गए हैं कि एक सामान्य नागरिक के लिए इसमें भाग लेना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। राजनीतिक दलों का बड़े चंदे पर निर्भर होने से यह संभावना ज्यादा होती है कि चुनाव जीतने के बाद उनकी

लाभ रिस-रिस कर रोजगार तथा वेतन के रूप में नीचे तक पहुंचेगा। इसके विपरीत संपत्ति का जमावड़ा ऊपर ही रुक गया और नीचे केवल बूढ़ें ही पहुंचेंगी। मुनाफे का उपयोग पुनर्विवेश और रोजगार सृजन के बजाय वित्तीय बाजारों में सट्टेबाजी और निजी संपत्ति बढ़ाने में किया गया।

हमारी कर प्रणाली, विशेष रूप से ‘वस्तु एवं सेवा कर’ यानी अप्रत्यक्ष करों का ढांचा, इस आग में घी डालने का काम करता है। अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि

लिए राशन की बात आती है, तो उसे ‘मुक्त की रेखड़ी’ कहकर अपमानित किया जाता है। यह दोहरा मापदंड देश की अर्थव्यवस्था और समाज में असंतुलन का कारण बनता है। असमानता का यह जहर सिर्फ बैंक खातों और आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह धीरे-धीरे समाज की नसों में उतर कर ‘अवरोध की समानता’ को भी खत्म कर देता है।

इसका सबसे ज्यादा और दूरगामी असर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी शिक्षा और

वास्तव में भेंट किसी अवसर विशेष में बंधा नहीं होता है, न ही इसकी कोई सीमा तय है। अब किसी के यहां किसी दूर प्रदेश से कोई अपना मिलने आता है, तो हम शहर विशेष की कोई खास और प्रसिद्ध चीज उन्हें भेंट करते हैं और वापसी की यात्रा के समय यह भी ध्यान में रखते हैं कि यात्रा में उन्हें किसी जरूरी सामान की कमी न हो। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम हर संभव छोटी-मोटी चीजों से उनका थैला भर देते हैं। ऐसे में मेहमान को सौंपे गए ये सामान भी भेंट की श्रेणी में ही माने जाते हैं। साथ जाने वाले ये भेंट हमारे एहसास को भी साथ-साथ लिए चलते हैं।

इसके अलावा, हम जब कभी नई जगह पर सैर-सपाटे के लिए निकलते हैं, तो वहां के प्रसिद्ध खान-पान, पहनावे, उपयोग की

कपड़े खरीदे जाते थे। बगैर नए कपड़ों के उन्हें विदा नहीं किया जाता था। यह एक तरह से सम्मान से भी जुड़ी बात होती थी। हमारे समाज में भेंट का एक स्वरूप और रिवाज हम भी है कि मान लीजिए कि हम किसी बर्तन में अपने जानने वाले को कुछ पकवान देते हैं और यह मानकर कि वह बर्तन हमें पकवान खाली कर वापस कर दिया जाएगा। मगर ऐसा अमूमन होता नहीं है कि वह बर्तन हमें खाली अवस्था में मिले। बदले में हमें यह बर्तन कुछ सामान से भरा हुआ ही मिलता है। अब यह रिवाज हमें किसी किताब में पढ़ाई नहीं गई है, न ही स्कूलों में भेंट संबंधी किसी अध्याय को शामिल किया गया है, लेकिन हमारे सामाजिक ताने-बाने में यह चीज गहराई से रम गई है कि हम इस परंपरा का पालन जरूर करते हैं।

देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान की मौलिक व्यवस्था पर ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर समानता के अधिकार को मजबूत करके, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में यह टकराव पैदा कर सकता है। हालांकि, धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक कमजोरी का प्रतीक है। यह ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य को एकसमान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करने को कहता है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ता है।

जहां तक समानता अधिकारों पर प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 21 को सशक्त संवैधानिक अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और 15 (भेदभाव निषेध) को मजबूत बनाएगा, क्योंकि यह धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसी के द्वारा तीन तलाक,

के बावजूद, राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और लंबित मामलों (5 करोड़ से अधिक) की भारी संख्या एकसमान कानून के कार्यान्वयन को जटिल बनाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति जरूरी हो सकती है, जो राजनीतिक मतभेदों से अवरुद्ध रहती है।

जहां तक संभावित प्रभाव की बात है तो ये अड़चने वास्तव में संविधान की विविधता-समर्थक भावना को दर्शाती हैं, जो एकता के साथ बहुलवाद को संतुलित रखती हैं। हालांकि, डिजिटल युग में एकसमान कानून आधिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिना व्यापक सहमति के यह संघीय तनाव

है, जो व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को संरक्षण प्रदान करते हैं। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 में नीति-निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है और मौलिक अधिकारों से टकरा सकता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने पर जोर दिया है (जैसे शाह बानो मामले में), लेकिन संघीय विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस राह की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

वहीं, व्यावहारिक और न्यायिक अड़चनों की बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका (अनुच्छेद 214) होने



भी पैदा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और उसकी राज्य सरकारों को इस बाबत आम सहमति तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक भारत, एक कानून में ही न केवल देश, बल्कि दुनिया की भी हित निहित, अंतर्निहित है।

असमान उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का सम्यक समाधान हो सकता है, जो महिलाओं के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को प्रभावित करते हैं। हालांकि, यदि गलत तरीके से लागू हुआ तो यह अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव का आरोप लगा सकता है।

जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव की बात है तो अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन का अधिकार देते हैं, जो यूसीसी से टकरा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो और सारला मुद्दल मामलों में यूसीसी की आवश्यकता बताई, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न मानते हुए संतुलित किया। फिर भी जनजातीय रीति-रिवाजों वाली समुदायों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। जहां तक अन्य मौलिक प्रावधानों पर यूसीसी के प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 21 को सशक्त संवैधानिक अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और 15 (भेदभाव निषेध) को मजबूत बनाएगा, क्योंकि यह धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसी के द्वारा तीन तलाक,

दूसरी कहानी बयां करती है। खेती, जो कभी सम्मान का पेशा थी, आज घाटे का सौदा बनकर रह गई है। खाद, बीज और ईंधन की लागत बढ़ रही है, लेकिन फसल का उचित ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ नहीं मिल पा रहा है। गांवों से शहरों की ओर हो रहा लोगों का अनियंत्रित पलायन इसी आर्थिक मजबूरी का परिणाम है। यह पलायन शहरों के बुनियादी ढांचे पर भी दबाव डाल रहा है और एक नए तरह के शहरी वर्ग-संघर्ष को जन्म दे रहा है।

तकनीक और वैज्ञानिक क्रांति ने भी अनजाने में ही सही, असमानता की एक नई परत जोड़ दी है। इसे ‘तकनीकी खाई’ या ‘डिजिटल विभाजन’ कहा जा रहा है। आज की दुनिया में सूचना ही शक्ति है, और यह शक्ति उनके पास है, जिनके पास आधुनिक संचार यंत्र, संगणक और तीव्र गति वाली इंटरनेट सुविधाएं हैं। ऐसे में सबसे पहले हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। सकल घरेलू उत्पाद से आगे बढ़कर हमें ‘मानव विकास’, ‘खुशहाली’ और ‘असमानता के स्तर’ को प्रगति का मुख्य पैमाना बनाना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी खर्च को एक बड़े हिस्से तक बढ़ाना होगा। साथ ही कर प्रणाली में भी सुधार करना होगा। रोजगार के मोर्चे पर हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा। उचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा, जहां हर किसी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो?

को समर्पित करते हैं। उपहार अपेक्षाओं से परे भी होते हैं और अमूमन आश्चर्यजनक सुखद अनुभव भी दे जाते हैं। हम किसी खास व्यक्ति को ही उपहार देना परमंद करते हैं और वह भी उनसे कुछ पाने की इच्छा के बगैर। पर हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी अति विशेष क्षण आते हैं, जब हमारे द्वारा दिए गए उपहार के बदले हमें एक अलग रूप में इसी तरह कुछ वापस जाता है, तो यह स्वयं में एक पूर्णता के भाव का सृजन करता है, जिसे शब्दों में बयां करना किसी दौर में संभव नहीं होता है। ऐसे क्षण जीवन के विशेष पल के रूप में याद की तरह बस जाते हैं और उम्र भर के लिए घर कर जाते हैं। इस तरह से मानव जीवन में उपहार का सरोकार समय और किसी भी मोल से परे है। बंधनों को मजबूत करते उपहार प्राचीन समाज से लेकर कारपोरेट जगत रूपी समाज में भी उतने ही प्रचलित और आपसी समनय को बेहतर करने के माध्यम हैं।

जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है तो जनवरी 2026 तक कोई नया निर्देश नहीं आया; क्योंकि कोर्ट यूसीसी को अनुच्छेद 44 के नीति-निर्देशक सिद्धांत के रूप में देखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन पर जोर देता है। यही वजह है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने 2024 में राज्य-स्तरीय यूसीसी लागू किया। समझा जा रहा है कि धीरे धीरे मोदी-शाह इसे पूरे देश में लागू करेंगे।

हालांकि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सभी जनहितकारी मामलों में यदि एक देश, एक कानून जैसे अग्रगामी प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है तो विगत 100 सालों से अनवरत रूप से जारी फूट डालो, शासन करो की नीति का जड़मूल से खाला हो जाएगा। यद्यपि मुझे भर चतुर सुजान विदेशी टुकड़े पर विरोध अवश्य करेंगे लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में थारा 370 हटवाकर एक विधान, एक निशान की राष्ट्रीय नीति लागू करवा सकते हैं तो उनके लिए एक देश, एक कानून को मूर्त रूप देना-दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्त कि इस मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस की नीति साफ और

ढांचे से जुड़ी मौलिक भावना को कमजोर करेगी। कुल मिलाकर, यूसीसी मौलिक अधिकारों को आधुनिक संदर्भ दे सकता है यदि सहमति-आधारित हो तो।

यही वजह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट निर्देश देने से इनकार किया है, बल्कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है। भले ही कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यूसीसी के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन कार्यपालिका को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जहां तक कोर्ट के रुख की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में यूसीसी लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि यह विधायी मामला है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रबुड़ ने मार्च 2023 में छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि यूसीसी संसद बनाएगी। इससे पहले आये निम्नलिखित प्रमुख फैसले में भी यूसीसी को मूर्त हो है। शाह बानो (1985), सरला मुद्दल (1995), और जॉन वल्लामड्रम (1997) जैसे मामलों में कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन निर्देश नहीं दिए। इसी प्रकार जनवरी 2023 में उत्तराखंड यूसीसी समिति

डीआईओएस पीएन सिंह के मार्ग दर्शन में कैरियर मेला का आयोजन छात्रों को ज्ञान के साथ विभिन्न कौशलों में करना है पारंगत : बीएसए

समग्र शिक्षा माध्यमिक की ओर से कैरियर गाइडेंस के लिए जनपद स्तरीय कैरियर मार्गदर्शन मेला लगा

मंत्र भारत संवाददाता
प्रयागराज। समग्र शिक्षा माध्यमिक की ओर से कैरियर गाइडेंस के तहत जनपद स्तरीय कैरियर मार्गदर्शन मेला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (निकट स्वरूप रानी), सिविल लाइंस, प्रयागराज में आज आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र - छात्राओं, कैरियर गाइडेंस से संबंधित विद्यालय नोडल शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं अभिभावक शामिल हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पीएन सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित कैरियर मार्गदर्शन मेले का शुभारंभ बीएसए अनिल कुमार, एसआरएन के वरिष्ठ सर्जन डा संतोष सिंह, प्रो शशिकांत त्रिपाठी कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज , सह जिला विद्यालय

निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। जीजीआईसी की प्रधानाचार्या नीलम मिश्रा ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। बैज अलंकरण किरन राय, लता कुमारी, स्काउट प्रभारी डॉ आकांक्षा केसरी ने किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। एडीआईओएस जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वागत अभिभाषण किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को ज्ञान के साथ साथ विभिन्न कौशलों में पारंगत बनाना समय की मांग है।इस दृष्टि से उन्हें विभिन्न अध्ययन और करियर क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित करियर मेला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । डॉ. शशिकांत त्रिपाठी प्रोफेसर एवं कृषि

विशेषज्ञ, डॉ जय सिंह एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्रीमती



आयुषी गौतम अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय, राहुल कुमार उप निरीक्षक उप्र पुलिस, डॉ सुधीर सिंह काउंसलर मॉडल करियर सेंटर तथा अन्य विषय विशेषज्ञों ने अपने - अपने क्षेत्र से

संबंधित उच्च अध्ययन एवं करियर विकल्पों की नवीन जानकारीयां देकर बच्चों को

विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। कैरियर गाइडेंस मेले का मुख्य आकर्षण मनोविज्ञान शाला, उप्र भारत स्काउट एंड गाइड, प्रयागराज, यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन, रेडियो अह्दा, एच.एन. सिंह डिग्री कॉलेज, ए के एस यूनिवर्सिटी सतना, मध्य प्रदेश, गणपत यूनिवर्सिटी गुजरात, पारुल यूनिवर्सिटी, लैटमै सलून , जन शिक्षण संस्थान. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एवं इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के स्टॉल रहे। आभार प्रदर्शन सह जिला विद्यालय निरीक्षक विजय सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी राजकीय विद्यालयों के वोकेशनल ट्रेनर्स के द्वारा भी अपने स्टाल लगाए गए।मेले में उपस्थित छात्र-छात्राओं तथा अभिभावकों ने सभी स्टॉल्स

का भ्रमण करके कैरियर गाइडेंस के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया । इस अवसर पीपी सिंह, शशिबाला चौधरी, मंजुलेश विश्वकर्मा , सुनील कुमार, मोहम्मद रफीक, ज्योति सिंह, सरिता वर्मा, प्रतिज्ञा चौहान, बी एस यादव, रवि भूषण, के पी सिंह, के के त्रिपाठी , सुषमा गुप्ता, नीलम चतुर्वेदी सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा लेखा प्रभारी विनय प्रकाश उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में रश्मि सिंह, डॉ रंजना यादव, इफ्फत जिया , वंदना, अनीता उत्तम, डॉ प्रीति मिश्रा, डा रेखाराम, मंजू श्रीवास्तव , संध्या सैलानी, शुभदर्शिनी सिंह, मनीषा, वंदना पांडे, मुकुला यादव, पुष्पा शुक्ला, ज्योति अग्रवाल, किरन गुप्ता, पल्लवी श्रीवास्तव, रूपांली, क्षमा, कीर्ति पाण्डेय, चारु तथा समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। संचालन डॉ प्रभाकर त्रिपाठी ने किया ।

कुंभ मेला 2025 में उत्कृष्ट सेवा पर उपेन्द्र नाथ ओझा सम्मानित मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र व कुंभ सेवा मेडल से किया अलंकृत

मंत्र भारत संवाददाता
प्रयागराज। कुंभ मेला 2025 के दौरान उत्कृष्ट, अनुकरणीय एवं सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों को सम्मानित किए जाने की कड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेला 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उपेन्द्र नाथ ओझा को प्रशस्ति पत्र एवं कुंभ सेवा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुंभ सेवा मेडल उपेन्द्र नाथ ओझा को पीयूष कान्त, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगाइड्स, पूर्वी ज्ञान तथा जिला कमांडेंट रंजीत सिंह द्वारा

पहनाया गया। सम्मान प्राप्त करते समय उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया।उत्कृष्ट सेवा का मिला प्रतिफल कुंभ मेला 2025 जैसे विशाल, संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण आयोजन में उपेन्द्र नाथ ओझा द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा भाव की अधिकारियों द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा



ब्राह्मण समाज द्वारा आशीर्वाद भवन में शतरंज प्रतियोगिता हुआ जिसमें अंडर 17 में सिद्धि अवस्थी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया

मंत्र भारत संवाददाता
रायपुर। 26 जनवरी के पावन अवसर पर बैरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें अंडर 17 में सिद्धि अवस्थी, (पिता राजीव अवस्थी) ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया पुरस्कार वितरण दिनांक 26, 01, 2026 को ही घोषित कर दिया गया था परंतु पुरस्कार वितरण के समय सिद्धि अवस्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण कल दिनांक 28, 01, 2029 को सिद्धि अवस्थी को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, और नगद 1100 रु पुरस्कार प्रमोद पाण्डेय के द्वारा प्रदान किया गया। कान्यकुब्ज , सभा शिक्षा मंडल सदैव समर्पण के साथ समाज सेवा और बच्चों के बौद्धिक संवर्धन के लिए कार्य करती है । इस अवसर पर सतीश चंद मिश्रा ने कहा प्रत्येक वर्ष अब हम बच्चों के लिए शतरंज प्रतियोगिता रखेंगे पुरस्कार वितरण के समय कान्यकुब्ज ब्रह्मा समाज से संजय अवस्थी , उपाध्यक्ष , राजेश दीक्षित सचिव, प्रमोद पांडे , सतीश मिश्रा , नीता अवस्थी , राधा तिवारी, राजीव अवस्थी (आजीवन सदस्य कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज,)एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रदेश संयोजक मुख्य रूप से उपस्थित थे।



यूजीसी एक्ट के खिलाफ सर्वर्ण आर्मी ने भरी हुंकार, सड़कों पर किया प्रदर्शन

सिद्धार्थनगर। जिले में यूजीसी एक्ट को लेकर सर्वर्ण समाज का आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। खेसरहा ब्याक क्षेत्र के बैलोहा बाजार में सर्वर्ण आर्मी के नेतृत्व में यूजीसी नियमों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की नीतियों के साथ-साथ भाजपा के खिलाफ भी तीखी नारेबाजी की।सैकड़ों की संख्या में जुटे सर्वर्ण समाज के लोग सेमरा मोड़ से पैदल मार्च करते हुए विकास खण्ड कार्यालय खेसरहा पहुंचे, जहां खण्ड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के कथित जनविरोधी नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी एक्ट शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला है और इससे छात्रों, शिक्षकों व समाज के भविष्य पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ेगा।प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा से जुड़े किसी भी निर्णय में व्यापक विमर्श आवश्यक है, लेकिन यूजीसी एक्ट में ऐसा नहीं हुआ। वहीं सर्वर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार दुबे ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।इस मौके पर सर्वर्ण आर्मी के जिला महासचिव शैलेंद्र कुमार पांडे, जिला महामंत्री ज्ञानेंद्र त्रिवेदी, जिला आईसीएल

प्रभारी राहुल पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय पांडे सहित अंकित पांडे, नित्यानंद उपाध्याय, सत्य प्रकाश पांडे, बालमुकुंद पांडे, विकास शुक्ला, अमित पांडेय, विकास त्रिपाठी, सनौ मिश्रा, आशुतोष पांडे, महेश, चंद्र भूषण पांडे, मोनू, आंकर नाथ पांडेय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे।प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित रही।



भारतीय समाचारपत्र दिवस की पत्रकारिता जगत को शुभकामनायें सकारात्मक पत्रकारिता समाज में विश्वास का निर्माण करती है : स्वामी चिदानन्द सरस्वती सत्य, साहस और सकारात्मक चेतना की अमर विरासत

मंत्र भारत संवाददाता
प्रयागराज/ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने आज भारतीय समाचार पत्र दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण पत्रकारिता जगत को शुभकामनायें देते हुये कहा कि भारत में पत्रकारिता की ऐतिहासिक यात्रा है। स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि समाचारपत्रों की राष्ट्रनिर्माण में अद्भुत भूमिका रही है। यह दिन पत्रकारिता के निर्भीक चेतना का उत्सव है जिसने भारत में सत्य, साहस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की नींव रखी।

भारतीय समाचारपत्र दिवस हमें उस युग में ले जाता है, जब शब्दों की ताकत से साम्राज्यों की नींव हिल जाया करती थी। 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ भारत का पहला समाचारपत्र 'हिक्की का बंगाल गजट' भारत ही नहीं एशिया का भी पहला मुद्रित समाचारपत्र था। समाचार पत्र प्रश्न पूछने का साहस रखने वाले पहली स्वतंत्र आवाज़ होते हैं।

स्वामी जी ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें भय में नहीं, बल्कि धर्म, दायित्व और जनहित में निहित हैं। समाचारपत्र केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज को दिशा दी, जनमानस को जागृत किया और



अनधिकृत रसायनों के उपयोग के चलते कंफर्ट अगरबत्ती पर लगा प्रतिबंध

मंत्र भारत संवाददाता
वाराणसी। भारत में घरेलू कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली गैर-लाभकारी संस्था, होम इंसेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन ने मच्छर भगाने वाली अवैध अगरबत्ती कंफर्ट पर सरकारी अधिकारियों की कार्यवाई का स्वागत किया है। कंफर्ट मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की बिक्री पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और दिल्ली में की जाती है, जिसका विनिर्माण मेसर्स धूप छांव कंपनी करती है। खुले बाज़ार से इकट्ठा किए गए नमूनों से पुष्टि हुई है कि यह उत्पाद खुले-

आम ग्राहकों को बेचा जा रहा था जबकि महाराष्ट्र कृषि विभाग की ओर से प्रयोगशाला में की गई जांच के दौरान कंफर्ट में डाइमेफ्लुथिन, एक अवैध रसायन पाया गया जिसके उपयोग की मंजूरी कंपनी ने पास नहीं थी। बताया जाता है कि कंफर्ट अगरबत्ती की बिक्री उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर से अन्य इलाकों में की जाती है।



स्वामी चिदानन्द सरस्वती सत्य, साहस और सकारात्मक चेतना की अमर विरासत

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया। महात्मा गांधी जी से लेकर लोकमान्य तिलक जी तक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचारपत्रों ने क्रांति का कार्य किया। स्वामी जी ने कहा कि आज के समय में, जब सूचनाओं की बाढ़ है और सोशल मीडिया के माध्यम से क्षणभर में खबरें फैल जाती हैं, तब समाचारपत्रों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्रकारिता का उद्देश्य सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि सत्य को प्रमाण, संतुलन और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना है। नकारात्मक नैरेटिव से समाज को भ्रमित करना आसान है, किंतु सकारात्मक, समाधान-केंद्रित पत्रकारिता ही राष्ट्र को सशक्त बनाती है।

स्वामी जी ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें भय में नहीं, बल्कि धर्म, दायित्व और जनहित में निहित हैं। समाचारपत्र केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज को दिशा दी, जनमानस को जागृत किया और

राज्य सभा सांसद अमरपाल मौर्या ने की एसआरएन को एम्स का दर्जा देने की मांग

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के प्रभारी व राज्य सभा सांसद अमरपाल मौर्या ने गुरुवार को राज्य सभा में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल को एम्स का दर्जा देने की मांग की राज्य सभा में मौर्या ने कहा कि प्रयागराज एक आध्यात्मिक प्रशासनिक और न्याय का केन्द्र है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हब है जो पूर्वांचल बुंदेलखंड और मध्य भारत को आपस में जोड़ता है यहां कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर के साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, और मध्य प्रदेश के सतना, रीवा और अन्य जिलों से लोग इलाज कराने प्रयागराज आते हैं इसलिए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जाए प्रयागराज में एम्स के माध्यम से शोध और विशेषज्ञता के नए द्वार खुलेंगे। जिस प्रकार रायबरेली और गोरखपुर में एम्स ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य असमानता को कम किया है उसी प्रकार प्रयागराज का एम्स संस्थान उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के बीच स्वास्थ्य निर्वात को भरेगा। इससे न केवल सस्ती व विश्वसनीय चिकित्सा सेवा मिलेगी आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन को भी नई शक्ति मिलेगी। प्रयागराज में एम्स की स्थापना कारणों नागरिकों के लिए एक न्याय पूर्ण कदम होगा। जिला मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी ने यह जानकारी दी।



संतों ने यूजीसी के नये कानून पर रोक का किया स्वागत कहा कि सरकार समाज को बांटने से बाज आये मठ मछली बंदर मठ मे खेली गयी फूल, अबीर-गुलाल की होली

है। संतों ने कहा कि सरकार का काम लोगों और समाज को एक करना है ना कि विघटन करना है, यह समाज और देश को बांटने वाला कानून था। इसको लागू करके सरकार समाज और देश के लोगों को क्या और कैसा संदेश देना चाहती थी। संतो ने कहा कि सरकार को इस तरह का कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि समाज बंटे और लोगों के बीच में सामाजिक विघटन बढे।

धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस नये कानून से जहां सामान्य वर्ग में व्यापक असंतोष था वही इस पर रोक लगाये जाने से राहत की



कलर्स पर शुरू हो रही है एक शक्तिशाली सेटबैक टू कमबैक यात्रा डॉ. आरंभी

मंत्र भारत संवाददाता

वाराणसी। कई महिलाओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि बलिदान हर समस्या का अंतिम समाधान है व अपना जीवन दूसरों का पोषण करने और दूसरों के घावों को भरने में बिताती हैं, जबकि चुपचाप अपनी पहचान को खत्म होने देती हैं। व्यक्तित्व को फिर से हासिल करने के लिए एक शक्तिशाली नई आवाज़ लाते हुए, कलर्स अपने नए शो डॉ. आरंभी के साथ साहस दूसरे मौके और आत्म-सम्मान को बचाए रखने का जीवन रक्षक डोज पेश करता है। यह दिलचस्प सेटबैक-टू-कमबैक ड्रामा व्याार, शादी और महत्वाकांक्षा की परतों को खोलकर दिखाता है कि किसी के जीवन को फिर से शुरू करने और अंदर से ठीक होने के लिए वास्तव में क्या चाहिए। कभी एक मशहूर गोल्ड मेडलिस्ट और एआईपीएमटी टॉपर, डॉ. आरंभी बलबीर चौधरी का भविष्य उम्मीदों से भरा था। "डॉ. आरंभी" में दूसरे मौके, वापसी, पछतावे और एक नई शुरुआत की तलाश की एक दिल को छू लेने वाली कहानी देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह शो आज रात प्रीमियर हो रहा है और उसके बाद हर सोमवार से शुक्रवार, रात 8:00 बजे कलर्स और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होगा।



कल्पवास से मिलती है आध्यात्मिक ऊर्जा : साध्वी रानी लक्ष्मी मां धर्म गुरु, अंतर्राष्ट्रीय साध्वी ने शिष्यों को दिया आशीर्वाद

प्रयागराज। प्रयाग के धर्म गुरु स्वामी रंजीत मिश्रा महाराज और जगदगुरु जगदमाता अंतर्राष्ट्रीय साध्वी रानी लक्ष्मी मां ने आज माघ मेला के सेक्टर-6 ओल्ड जीटी रोड पर लगे शिविर में देश के कोने - कोने से बड़ी संख्या में आये शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए उनका मंगल की कामना किया। धर्म गुरु स्वामी रंजीत मिश्रा महाराज ने कहा कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थंजय प्रयागराज का माघ मेला सबसे उत्तम तपस्या का स्थल है ऐसे में सभी सनातन धर्मावलंबियों को माघ मास में आकर कम से कम एक बार कल्पवास करते हुए कथा, प्रवचन सुनते हुए दान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीर्थंजय प्रयागराज भगवान ब्राह्म की तपस्थली रही है उन्होंने सृष्टि

निर्माण के लिए यहां के दशाश्वमेध घाट (दारागंज) में पहला यज्ञ किया था, भगवान विष्णु ने अक्षयवट पर बच्चे के रूप में अगुला चूसते हुए विश्व को सृष्टि निर्माण का नया संदेश दिया था ऐसे में तीर्थंराज सबसे बड़ी और सबसे पवित्र तपस्थली है। जगदगुरु जगदमाता अंतर्राष्ट्रीय साध्वी रानी लक्ष्मी मां ने बताया कि बचपन से मेरा धर्म की तरफ रुझान था जिससे आज वेद, वेदांग, उप निषद, श्रीमदभागवद

गीता का अध्ययन कर बहुत कुछ सनातन धर्म के बारे मे ज्ञान प्राप्त किया हू। उन्होंने बताया कि माघ मास में एक माह कल्पवास करके धार्मिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त किया जिससे अब विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी और लोगों को जोड़ते हुए सनातन धर्म को और मजबूत करूंगी। उन्होंने बताया कि शिविर मे पूजन, हवन और विशाल भण्डारा माघी पूर्णिमा तक चलता रहेगा।



भाजपा से लेकर फंट तक की गणित बिगड़ी

भिवंडी में सेकुलर फ्रंट को बड़ा झटका, सपा की साइकिल कांग्रेस खेमे से खिसकी! 13 नगरसेवकों का नया फ्रंट बना ‘किंगमेकर’

भिवंडी (संवाददाता) **▶ मंत्र न्यूज**

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में सेकुलर फ्रंट के जरिए मेयर बनाने का कांग्रेस का सपना फिलहाल टूटता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के इस फ्रंट से अलग हो जाने के बाद अब पूरा गणित कोणार्क विकास आघाड़ी के चार नगरसेवकों पर टिक गया है। सपा की साइकिल के कांग्रेस खेमे से खिसकते ही सत्ता की बाजी पूरी तरह पलट गई है।

90 सीटों वाली भिवंडी मनपा में कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली है, जबकि राकांपा (शरद पवार) के 12 और समाजवादी पार्टी के 6 नगरसेवकों को मिलाकर सेकुलर फ्रंट का आंकड़ा 46 तक पहुंच रहा था, जिसे स्पष्ट बहुमत माना जा रहा था। इसी भरोसे पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष व पूर्व विधायक एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, सपा विधायक रईस कासम शेख, राकांपा (शरद पवार) के शहर जिला अध्यक्ष

शोहेब खान गुड्डू और सपा प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव ने संयुक्त रूप से सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाने का दावा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। लेकिन



इसी दौरान बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया। भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जीते समाजवादी पार्टी के सभी 6 नगरसेवक कांग्रेस खेमे से खिसक गए। चर्चा है कि भिवंडी विकास आघाड़ी के 3, कोणार्क विकास आघाड़ी के 4 और समाजवादी पार्टी के 6, कुल 13 नगरसेवकों ने मिलकर अलग से एक

नया फ्रंट बना लिया है। यही नया फ्रंट अब भाजपा महायुति और कांग्रेस-राकांपा युक्त सेकुलर फ्रंट-दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, इस संयुक्त फ्रंट में

है कि सपा विधायक रईस कासम शेख ने भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस और राकांपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, जिसके चलते सभी सपा उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद विधायक शेख के जीते समर्थक कांग्रेस और राकांपा के नगरसेवकों द्वारा कथित तौर पर साइकिलें तोड़े जाने की घटनाएं सामने आईं, जिससे समाजवादी पार्टी की भारी बदनामी हुई। इसी नाराजगी के चलते पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और नगरसेवक विधायक शेख से दूर होते चले गए और ‘साइकिल तोड़ने’ का बदला लेने के इरादे से सेकुलर फ्रंट से किनारा कर लिया।अब राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के नारायण चौधरी, कोणार्क विकास आघाड़ी के विलास आर. पाटिल या मयुरेश पाटिल, अथवा भिवंडी विकास आघाड़ी के पूर्व मेयर जावेद दलवी एक बार फिर भिवंडी के मेयर की कुर्सी संभाल सकते हैं। भिवंडी की सत्ता में कौन बैठेगा, इसका फैसला अब इन 13 नगरसेवकों के रुख पर टिका हुआ है।

महर्षि आजाद राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शशांक इलेवन और रायबरेली सेमीफाइनल में मास्टर एकेडमी व झारखंड का सफर समाप्त

मंत्र भारत संवाददाता भदोही। सुरियावां क्षेत्र स्थित महर्षि आज़ाद स्टेडियम, मेढ़ी में आयोजित महर्षि आज़ाद राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को खेले गए दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शशांक इलेवन मोड़ और रायबरेली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। हार के साथ मास्टर क्रिकेट एकेडमी सुरियावां और झारखंड की टीमें प्रतियोगिता से बाहर हो गईं।

पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मास्टर एकेडमी की टीम 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 109 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सूरत

ने 20 गेंदों पर 38 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि अभिजीत ने 26 गेंदों में 19 रन बनाए। शशांक इलेवन की ओर से मयंक दुबे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 8 रन देकर 3 विकेट झटके। कुलदीप मिश्रा और अभिनव तिवारी को दो-दो विकेट मिले।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी शशांक इलेवन की टीम ने 13.5 ओवर



में 4 विकेट खोकर 114 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। हर्षित तिवारी ने 36 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की शानदार पारी खेली। मनु राजा ने 14 गेंदों में 26 रन और मयंक दुबे ने 14 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर टीम की जीत को आसान बना दिया।

दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रायबरेली की टीम ने झारखंड को

एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड की पूरी टीम 18.3 ओवर में मात्र 81 रन पर सिमट गई। झारखंड की ओर से अभिषेक ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। रायबरेली के लिए उमर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट झटके। अमित वर्मा और आनंद प्रकाश ने दो-दो विकेट लेकर विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोक दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए रायबरेली की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 6.3 ओवर में 85 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। उमर ने नाबाद 46 रन की तूफानी

पारी खेली, जबकि विकेटकीपर सक्षम ने नाबाद 32 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतियोगिता के चीफ ऑर्गेनाइजर प्रतीक महर्षि दुबे द्वारा मोहम्मद उमर को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर समिति अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सचिव अमर बहादुर सिंह, विजयशंकर राय, राजमणि पांडेय, मथुरा प्रसाद यादव, दिनेश यादव ‘दादा’, जर्मीदार बिंद, राजकुमार सरोज, जेपी सिंह, श्याम बहादुर यादव, परमेंद्र गौतम, राकेश वर्मा, मनोज गौतम, अतुल सिंह, नितेश श्रीवास्तव, सनी सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

गोरखपुर ने देवरिया को चार विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जनपद के वीरेंद्र ग्रामीण स्टेडियम छतहरी शोहरतगढ़ में बृहस्पतिवार को सिद्धार्थनगर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित गौतम बुद्ध ऑल इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-4 के तहत गोरखपुर और देवरिया के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। शानदार प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर की टीम ने देवरिया को चार विवेकट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

गोरखपुर के कप्तान नीरज यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरिया की टीम ने निधरित 16 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन

बनाए। देवरिया की ओर से आशीष यादव ने शानदार 64 रन की पारी खेली। वहीं विवेक सिंह ने 24 रन और शाकिर अली ने 18 रनों का योगदान दिया। गोरखपुर की गेंदबाजी में अनुराग यादव और शिवम ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि आदित्य और संदीप को एक-एक सफलता मिली।1136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरखपुर की टीम ने 15.4 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। गोरखपुर की ओर से अंकुर ने 30 रन, आर्यन सिंह ने 22 रन और आनंद दुबे ने नाबाद 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। देवरिया की तरफ से आकाश और सुजल ने दो-दो विकेट लिए जबकि विवेक सिंह और शाकिर अली को एक-एक विकेट



मिला।

मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए गोरखपुर के अनुराग यादव को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया। गोरखपुर व देवरिया मैच के मुख्य अतिथि असरफ मेमोरियल हॉस्पिटल शोहरतगढ़ के सर्जन डॉ. नसीम अहमद ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि सर्जन डॉ नसीम अहमद, नपं अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, सिद्धार्थनगर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, मनीष श्रीवास्तव, विवेक त्रिपाठी, विपिन त्रिपाठी, राजेश उपाध्याय, बेचन यादव, केशव यादव, राहुल चौधरी, चंदन पांडे, वकील खान, बाबूजी अंसारी, गुलाम गौस, चंद्र प्रकाश उर्फ चिट्ठू, केशवराम यादव, पप्पू यादव, राकेश राज, रामानंद पाण्डेय, पियुष सिंह, मनोज कुमार सहित कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।

पुलिस ने नाबालिक के अपहरण का आरोपी हुआ गिरफ्तार

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहतगढ़ के कुशल निर्देशन व अभय सिंह थानाध्यक्ष कठेला समय माता के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-06/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को ग्राम सौरहवा ग्राण्ट के पास से उप निरीक्षक आनंद कुमार , कास्टेबल शुभम सिंह ने इरशाद पुत्र छेदी साकिन सौरहवाग्रान्ट टोला धुसीजोत को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा।



कर्म ही साधन, कर्म ही साध्य – इं. देवेन्द्र नाथ शुक्ला ‘कृष्णार्पित’

प्रयागराज, माघ मेला। माघ मेला क्षेत्र के हर्षवर्धन मार्ग स्थित कृष्णार्पित ट्रस्ट के पंडाल में आयोजित श्रीमद्भगवत कथा के तृतीय दिवस पर श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का शास्त्रीय, तात्त्विक एवं गूढ़ विवेचन प्रस्तुत किया गया। कथा-वाचन इं. देवेंद्र नाथ शुक्ला ‘कृष्णार्पित’ द्वारा वेद-उपनिषद् परंपरा के आलोक में किया गया। कथावाचक ने प्रतिपादित किया कि द्वितीय अध्याय में आत्मा की नित्यता, ब्राह्मी स्थिति एवं निश्चयात्मिका बुद्धि का उपदेश देकर भगवान श्रीकृष्ण तृतीय अध्याय में कर्म के स्वरूप, उसकी अनिवार्यता तथा उसके मोक्षोपयोगी रूप को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन का संशय और श्रीकृष्ण का उत्तर अर्जुन ज्ञान की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए प्रश्न करता है- यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त

होने की प्रेरणा क्यों? इस पर भगवान श्रीकृष्ण उद्घोष करते हैं- ‘न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्’। अर्थात् संसार में कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी अकर्म नहीं रह सकता। नियत कर्म एवं स्वधर्म का प्रतिपादन कथावाचक ने कहा कि श्रीकृष्ण अर्जुन को उसके नियत कर्म का स्मरण कराते हैं। स्वधर्मानुसार किया गया कर्म ही श्रेयस्कर है, भले ही वह कठिन प्रतीत हो। ‘श्रेयान्स्वधर्मात् विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्’। परधर्म का आचरण भयावह है, जबकि स्वधर्म आत्मोद्धार का साधन है। कर्मयोग का सिद्धांत गीता के अनुसार कर्म त्याग का विषय नहीं, अपितु कर्म में आसक्ति का त्याग



आवश्यक है। यज्ञार्थ किया गया कर्म बंधनरहित होता है, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनता है। कथावाचक ने कहा कि कर्मयोग आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, जिसमें कर्म करते हुए भी साधक अंतःकरण से निर्लिप्त रहता है। लोकसंग्रह और महापुरुषों का आदर्श श्रीकृष्ण जनकादि राजपि्यों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी लोकसंग्रह के लिए कर्म करते हैं। ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तत्तदेवतरो जनः’। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही समाज का मार्गदर्शन करता है। कर्म का शत्रु - काम कथा में कर्म के प्रधान शत्रु काम

का शास्त्रीय विश्लेषण करते हुए कहा गया- काम ही क्रोध का कारण है और वही ज्ञान को आच्छादित करता है। ‘काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। इंद्रिय, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ही साधक इस शत्रु पर नियंत्रण कर सकता है। प्रकृति और अहंकार का विवेचन कथावाचक ने बताया कि समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। अहंकारवश स्वयं को कर्ता मानने से ही बंधन उत्पन्न होता है। ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि- कर्म प्रकृति करती है, वह स्वयं केवल साक्षी मात्र है। कर्मयोग का परम लक्ष्य कथा का उपसंहार करते हुए इं. देवेंद्र नाथ शुक्ला ‘कृष्णार्पित’ ने कहा कि- कर्मयोग आत्मकल्याण एवं लोककल्याण

का सेतु है। कर्म में स्थित होकर ही मनुष्य मोक्षमार्ग पर अग्रसर होता है। तृतीय दिवस की यह कथा गीता के कर्मयोग को केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, अपितु मानव जीवन की अनिवार्य का सेतु है। कर्म में स्थित होकर ही मनुष्य मोक्षमार्ग पर अग्रसर होता है। तृतीय दिवस की यह कथा गीता के कर्मयोग को केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, अपितु मानव जीवन की अनिवार्य

साधना के रूप में प्रतिष्ठित करती है। कथा के अंत में पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं ने ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’, ‘जय श्रीकृष्ण’ एवं ‘हर-हर गंगे’ के घोष से वातावरण का सम्मान आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया।

गुजरात की झांकी का जलवा, लगातार चौथे साल पॉपुलर चॉइस में नंबर-1

नई दिल्ली (एजेंसी)। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक बार फिर गुजरात का डंका बजा है। गुजरात की झांकी ‘स्वतंत्रता का मंत्र वंदेमातरम’ ने देशवासियों का दिल जीतते हुए ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’ कैटेगरी में लगातार चौथे साल प्रथम स्थान हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने इस शानदार जीत पर सूचना विभाग को बधाई देते हुए इसे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रभक्ति का सम्मान बताया है। यहां इस ऐतिहासिक जीत की पूरी जानकारी दी गई है। गुजरात की झांकी को मिला बंपर जनसमर्थन केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा माईगव पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन वोटिंग में गुजरात ने एक्टरफा जीत दर्ज की। कुल मतों में से अकेले गुजरात को 43 प्रतिशत वोट मिले।

कशेली बस स्टैंड के सामने सरेआम चैन स्नैचिंग कर बाइक सवार बदमाश हुए फरार,फैला भय भिवंडी (संवाददाता)

▶ मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी कशेली बस स्टैंड परिसर में बुधवार शाम बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने सरेआम एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। जिसकी कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई जा रही है।दिनदहाड़े घटी इस घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है।पुलिस अज्ञात स्नैचरों पर केस

दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार भिवंडी के गुंदवली गांव निवासी मेथा गोविंद पाटील (46) अपने भतीजे की शादी के निमंत्रण पत्र बांटने के लिए कशेली गए थे। 28 जनवरी की शाम करीब 7.15 बजे वे कशेली बस स्टैंड के सामने एक रिक्षा में बैठे हुए थे। इसी दौरान काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवक सामने से आए और बाइक पर पीछे बैठे युवक ने अचानक मेथा के गले से करीब

एक तोला वजन की सोने की चेन जबरन खींच ली।वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। नारपोली पुलिस ने अज्ञात झपटमार आरोपियों के खिलाफ छीनैती का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दिया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक आकाश पवार कर रहे हैं।

चाकू की नोक पर कार में बैठे ठेकेदार से 50 हजार और टैब की जबरन छिनैती

भिवंडी। नाशिक-मुंबई रोड पर सरवली पाड़ा इलाके में मंगलवार शाम बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू दिखाकर एक ठेकेदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने कार में बैठे व्यक्ति के हाथ से काली बैग छीन ली, जिसमें करीब 50 हजार रुपये नकद और, सैमसंग कंपनी का टैब था।इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बपुलिस के अनुसार, नाशिक निवासी सुभाष दिनानाथ प्रसाद (42), पेशे से कंस्ट्रक्शन ठेकेदार, अपने मित्र अंकुश बोडके

के साथ कार (एमएच-15 एफएफ 8710) से मुंबई जा रहे थे। 27 जनवरी की शाम करीब 7.30 बजे सरवली पाड़ा स्थित बाबोसा कंपाउंड के पीछे उनकी कार रुकी। इसी दौरान अंकुश बोडके प्राकृतिक आवश्यकता के लिए कार से उतरकर कुछ दूरी पर चले गए, जबकि सुभाष कार में अकेले बैठे थे।इसी दौरान काले रंग की एफ-शेड मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवक कार के पास पहुंचे और पीछे बैठे बदमाश ने सुभाष के हाथ में मौजूद काली बैग जबरन खींचने

की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि चाकू दिखाकर धमकाया और बैग छीनकर नाशिक की दिशा में तेज रफ्तार से फरार हो गए। घटना की शिकायत कोरनांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक रोहन गायकवाड़ कर रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।

मुंबई कमाने निकल युवक की तालाब में मिली लाश

सिद्धार्थनगर। जिले के शिवनगर डिडई थाना क्षेत्र के असनहरा गांव निवासी हकीजुल्ला पुत्र मो0 रफीक ने थाने पर लिखित सूचना दी गयी कि उसके बड़े भाई उताउल्लाह पुत्र मो0 रफीक उम्र 25 वर्ष का शव असनहरा गांव के दक्षिण तालाब मे पड़ा था

अत्ताउल्लाह अपने घर से मुंबई के लिए रोजी रोटी के लिए घर से निकला था और उसकी मोबाइल बंद हो गई। शव मिलने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर उप निरीक्षक शिवनारायन यादव, उप निरीक्षक राजीव जी भट्ट, उप निरीक्षक

मृत्युंजय मिश्रा मय फोर्स के मौके पर पहुंच कर विधिक कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार मौर्या ने बताया की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है पीएम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है।



महाप्रबंधक उत्तर रेलवे ने भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर-कटरा खंड का निरीक्षण किया; शून्य से नीचे तापमान में कर्मचारियों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता

नई दिल्ली।उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा ने आज श्रीनगर से कटरा रेल खंड का गहन निरीक्षण किया। यह निरीक्षण ऐसे महत्वपूर्ण समय में किया गया है जब कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी और शून्य से नीचे (सब-ज़ीरो) तापमान के कारण मौसम की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। प्रमुख स्टेशनों और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण अपने दौरे के दौरान, महाप्रबंधक ने श्रीनगर, पंपोर, अनंतनाग और काजीगुंड सहित कई प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीषण सर्दी के बावजूद यात्रियों को असुविधा न हो। श्री वर्मा ने विभिन्न सुरंगों और पुलों पर चल रहे रखरखाव और निर्माण कार्यों की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया।

दिल्ली में पांच स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद अफवाह निकली

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार सुबह पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिये मिली धमकियां जांच के बाद अफवाह साबित हुई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, इन धमकियों के बारे में उन्हें सुबह करीब 8.30 बजे सूचना मिली जिसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और परिसरों की व्यापक तलाशी ली गयी।

डीएफएस ने पुष्टि की कि दिल्ली कॅंटीनमेंट स्थित लॉरेटो कॉन्वेंट, चित्ररंजन पार्क के डॉन बोस्को तथा आनंद निकेतन और द्वारका में स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल परिसरों को धमकियां मिली थीं।

वहीं, दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय ने अभिभावकों को एक संदेश भेजकर घटना के बारे में सूचित कर दिया था। इसी के साथ पुलिस और दमकल विभाग को भी सूचना दी थी जिसके बाद सभी परिसर को खाली कराकर जांच की गई।

जापानी प्रधानमंत्री ने चीन को दिखाई आंख कहा-ताइवान युद्ध में अमेरिका पर हमला हुआ तो देंगे कड़ा जवाब

टोक्यो (एजेंसी)। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ताइवान को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर ताइवान में कोई बड़ा संकट पैदा होता है और वहां अमेरिकी सेना पर हमला किया जाता है, तो जापान मूकदर्शक नहीं बनेगा, बल्कि दखल देगा। टोक्यो में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान ताकाइची ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर जापान ने कुछ नहीं किया तो अमेरिका के साथ उसका सुरक्षा गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ताइवान का मामला सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि जापान की सुरक्षा और उसके अंतरराष्ट्रीय रिश्तों से जुड़ा हुआ है।

निक्केई एशिया के मुताबिक, ताकाइची ने यह भी कहा कि आपात स्थिति में ताइवान में फंसे जापानी और अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित

मौलाना की शहबाज सरकार को खुली धमकी पाकिस्तान में ‘खुलेआम तोड़ेंगे’ कानून, 10 साल की लड़कियों की कराएंगे शादी

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान में एक बार फिर कड़ुरपंथ और कानून के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। जमीत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शारीक सरकार द्वारा लाए गए पारिवारिक कानून सुधारों का खुला विरोध करते हुए विवादास्पद बयान दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बाल विवाह रोकथाम बिल 2025 के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वह इसके विरोध में 10 साल तक के बच्चों की शादी कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह इन शादियों में स्वयं

शामिल होंगे और सरकार के कानून को ‘खुलेआम तोड़ेंगे’।

पाकिस्तानी संसद ने हाल ही में घरेलू हिंसा (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम 2026 पारित किया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा को अपराध घोषित किया गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद क्षेत्र में शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने इन कानूनों को ‘गैर-इस्लामी और असंवैधानिक’ बताते हुए कहा कि संसद को धार्मिक

निरीक्षण का एक मुख्य आकर्षण महाप्रबंधक का कर्मचारियों (ग्राउंड स्टाफ) और ट्रैक मेंटेंर्स के साथ संवाद

था। जमा देने वाली ठंड में काम करने के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए, श्री वर्मा ने सर्दियों के दौरान पटरियों के रखरखाव में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में उनसे सीधा फीडबैक

लिया। ‘शून्य से नीचे के तापमान में अथक परिश्रम करने वाले हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि है,’ श्री वर्मा ने कहा। उन्होंने साथ आए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को सभी आवश्यक शीतकालीन उपकरण और सुरक्षा गियर तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए ट्रैक के रखरखाव को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कार्यबल पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। निरीक्षण का समापन करते हुए, महाप्रबंधक ने क्षेत्र में चल रही अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त समय सीमा का पालन करने की सलाह दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेल नेटवर्क मजबूत बना रहे और मौसम के कारण विकास कार्यों में बाधा न आए।

हालांकि इस बार वीडियो में जो दृश्य दिखे हैं, उन्होंने अटकलों को और तेज कर दिया है। खासकर सरगोधा के मुशाफ एयरबेस के आसपास के इलाके के साथ राफेल, सुखोई, जगुआर और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की झलक दिखाई गई और पक्ति उभरी- शांति के प्रवर्तक। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह प्रश्न फिर से जोर पकड़ गया है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु भंडारण क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना बनाया

पड़ै। वीडियो में महिषासुर मर्दिनी की पृष्ठभूमि धुन के साथ सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ते लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक

हथियार प्रणाली दिखाई गई। राफेल पर मेटिओर मिसाइल, सुखोई पर ब्रह्मोस और अस्त्र, जगुआर पर गहरी मार करने वाली मिसाइलें और अन्य सटीक हथियारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय वायुसेना किसी भी स्तर

भारतीय वायुसेना के वीडियो से उड़ गये पाकिस्तान के होश, किराना हिल्स, सरगोधा एयरबेस और नूर खान एयरबेस बने थे निशाना

था? हम आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष ऑपरेशन के बाद एयर मार्शल एके भारतीय ने स्पष्ट कहा था कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। वायुसेना अब भी आधिकारिक रूप से इसी रुख पर कायम है।

हालांकि इस बार वीडियो में जो दृश्य दिखे हैं, उन्होंने अटकलों को और तेज कर दिया है। खासकर सरगोधा के मुशाफ एयरबेस के आसपास के इलाके के साथ राफेल, सुखोई, जगुआर और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की झलक दिखाई गई और पक्ति उभरी- शांति के प्रवर्तक। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह प्रश्न फिर से जोर पकड़ गया है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु भंडारण क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना बनाया

पड़ै। वीडियो में महिषासुर मर्दिनी की पृष्ठभूमि धुन के साथ सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ते लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक

एक हफ्ते में दूसरा भीषण हादसा: दक्षिण अफ्रीका में टैक्सी-ट्रक टक्कर में 11 की मौत

केप टाउन (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूर्वी व्वाज़ुलू-नताल प्रांत में एक मिनीबस टैक्सी और ट्रक की जोरदार टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक स्कूली बच्चा भी शामिल है।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में भी ताकाइची ने जापानी संसद में कहा था कि ताइवान के खिलाफ चीन की नाकेबंदी या सैन्य कार्रवाई जापान के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकती है। उस बयान पर चीन ने कड़ी नाराजगी जताई थी और दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था।चीन के दबाव के बाद ताकाइची ने दिसंबर में कहा था कि जापान का ताइवान पर रुख 1972 से नहीं बदला है, लेकिन अब उनके ताजा बयान से साफ है कि टोक्यो ताइवान के मुद्दे पर पीछे हटने के मूढ़ में नहीं है। इससे एक बार फिर चीन-जापान रिश्तों में तल्खी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

यूनस का कबूलनामा : धोखाधड़ी में वर्ल्ड चैंपियन बना बांग्लादेश, दुनिया में बुरी तरह गिरी देश की साख

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनस ने एक चौकाने वाला और शर्मनाक खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेश ने धोखाधड़ी और जालसाजी के कारण ‘दुनिया के चैंपियन’ जैसी बदनामी कमा ली है। उनके मुताबिक, बड़े पैमाने पर नकली दस्तावेजों ने देश की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को गहरा नुकसान पहुंचाया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यूनस ने कहा, ‘सब कुछ नकली है पासपोर्ट नकली, वीजा नकली। कई देश हमारे पासपोर्ट स्वीकार ही नहीं करते।’ उन्होंने यहां तक कहा कि बांग्लादेश

नई दिल्ली। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य समारोह में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक भव्यता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस वर्ष की परेड में राज्यों के चित्ररथों में महाराष्ट्र वेड चित्ररथ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित परिणामों वेड अनुसार इस श्रेणी में जम्मू-कश्मीर राज्य ने द्वितीय तथा केरल राज्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष महाराष्ट्र ने ‘गणेशोत्सव : आत्मनिर्भरता का प्रतीक’ इस संकल्पना पर आधारित चित्ररथ प्रस्तुत किया था।

गणतंत्र दिवस पर परेड में महाराष्ट्र का चित्ररथ देश में सर्वश्रेष्ठ

संदेश है। यह संदेश दुश्मन के लिए भी है और दुनिया के लिए भी। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना ने यह दिखा दिया है कि वह शांति की सबसे मजबूत गारंटर है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वही शक्ति विनाशकारी प्रहार में भी बदल सकती है।

किराना हिल्स को लेकर बना रहस्य दरअसल रणनीतिक धुंध का हिस्सा है। आधुनिक युद्ध केवल बम और मिसाइल से नहीं, बल्कि अनिश्चितता और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ा जाता है। जब भारत यह कहता है कि उसने उस क्षेत्र पर हमला नहीं किया, लेकिन दृश्य और उपग्रह चित्र कुछ और संकेत

नई दिल्ली। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य समारोह में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक भव्यता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस वर्ष की परेड में राज्यों के चित्ररथों में महाराष्ट्र वेड चित्ररथ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित परिणामों वेड अनुसार इस श्रेणी में जम्मू-कश्मीर राज्य ने द्वितीय तथा केरल राज्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष महाराष्ट्र ने ‘गणेशोत्सव : आत्मनिर्भरता का प्रतीक’ इस संकल्पना पर आधारित चित्ररथ प्रस्तुत किया था।

इस चित्ररथ के माध्यम से महाराष्ट्र की समृद्ध लोकसंस्कृति, गणेशोत्सव की सामाजिक परंपरा तथा इसके माध्यम से मिलने वाला आर्थिक रोजगार और

आत्मनिर्भरता का संदेश अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। चित्ररथ पर विराजमान भव्य गणेश प्रतिमा, पारंपरिक ढोल-ताशा पथक और लेज़ीम खेलने

वाले कलाकारों के जोश ने पूरे परेड मार्ग को उत्साह से भर दिया। इस प्रभावी प्रस्तुति के कारण निर्णायक मंडल ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समूह में महाराष्ट्र के चित्ररथ को सर्वश्रेष्ठ चित्ररथ के रूप में चयनित किया। केवल राज्य श्रेणी में ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इसमें सैन्य बलों की श्रेणी में ‘भारतीय नौसेना’ तथा अर्धसैनिक बलों की श्रेणी में ‘दिल्ली पुलिस’ की परेड को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। वेड द्रीय मंत्रालयों वेड समूह में संस्ृति मंत्रालय वेड चित्ररथ को प्रथम पुरस्कार

प्राप्त हुआ, जबकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और ‘वंदे मातरम्’ नृत्य समूह को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

फिल्म ‘धुरंधर’ का एक्टर गिरफ्तार, 10 साल तक नौकरानी का करता रहा शोषण

नई दिल्ली (एजेंसी)। फिल्म इंडस्ट्री से एक गंभीर मामला सामने आया है। हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आए अभिनेता नदीम खान को घरेलू सहायिका से शादी का वादा कर वर्षों तक यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, 41 वर्षीय महिला ने अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 22 जनवरी को नदीम खान को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि खान ने उससे शादी का वादा कर करीब 10 वर्षों तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत के मुताबिक, महिला अलग-अलग अभिनेताओं के यहां घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। इसी दौरान वर्षों पहले उसकी मुलाकात नदीम खान से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। महिला का आरोप है कि अभिनेता ने भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और इसी भरोसे के आधार पर उसने शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने मालवानी स्थित अपने घर और वसौला स्थित अपने आवास पर कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में अभिनेता ने शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने शुरुआत में वसौला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, चूंकि पहला कथित अपराध मालवानी क्षेत्र में हुआ था और पीड़िता भी उसी इलाके की रहने वाली है, इसलिए मामले को ‘जीरो एफआईआर’ के तहत मालवानी पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Facebook: <https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044>

Twitter: <https://twitter.com/mantrabharatt~8tJONQ7H-h6EKYqqp2tVMw&s=08>

Mobile No: **7007837917**

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहेपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शा.प.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शा.प.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्याकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागगंज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालय: 80ए मेहंदीरी, तेलियरगंज, प्रयागगंज-211004 (नोट: कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)